श्रद्धालुओं की सुविधा पर मुख्यमंत्री का फोकस

- मुख्यमंत्री ने क्षिप्रा नदी पर 29 किमी लंबे घाट देखे
- घाट पर टॉयलेट और पहुंच मार्ग बनेंगे
- अंगारेश्वर पर पूजन अर्चन पश्चात सिंहस्थ पर चर्चा

नवभारत न्यूज

उज्जैन. सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत क्षिप्रा नदी के घाटों का निर्माण तेज़ी से किया जा रहा है. गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अंगारेश्वर महादेव मंदिर में पूजा-अर्चना करने के बाद क्षिप्रा नदी पर निर्माणाधीन नए घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक निर्देश दिए.

अंगारेश्वर और सिद्धवट मंदिर के बीच बन रहे घाटों का निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंहस्थ के दौरान करोड़ों श्रद्धालु स्नान के लिए उज्जैन आते हैं, इसलिए घाटों पर सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाए. उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्य घाटों के आसपास 200 मीटर की दूरी पर श्रद्धालुओं के लिए कपड़े बदलने की व्यवस्था, टॉयलेट और अन्य सुविधा घर बनाए जाएं, ताकि स्नान करने आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो,

एप्रोच रोड बनाओ-घाटों तक पहुंचने के लिए भी बेहतर व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 500 मीटर की दूरी पर सीढ़ियां या अन्य पहुंच मार्ग बनाए जाएं, ताकि श्रद्धालु आसानी से घाट तक पहुंच सकें और स्नान के बाद सुरक्षित तरीके से वापस जा सकें. घाटों पर श्रद्धालुओं के बैठने और विश्राम करने की भी व्यवस्था विकसित की जाएगी.

सीएम ने किया था भूमि पूजन -यह वही घाट हैं जिनका भूमि पूजन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 31 मई 2025 को किया था. तब से निर्माण कार्य लगातार जारी है. घाटों के निर्माण के बाद एक समय में बड़ी संख्या में श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, जिससे सिंहस्थ के दौरान भीड़ प्रबंधन आसान होगा.

प्लेटफॉर्म भी बनाएंगे

निरीक्षण के दौरान अंगारेश्वर और सिद्धवट मंदिर के बीच बन रहे नए पुल की प्रगति भी देखी गई. कलेक्टर रौशन कुमार सिंह ने बताया कि पुल बनने के बाद दोनों प्रमुख धार्मिक स्थलों के बीच आवागमन आसान होगा और श्रद्धालुओं को एक नया वैकल्पिक मार्ग मिलेगा. घाटों पर लगभग 5 मीटर चौड़ा प्लेटफॉर्म भी बनाया जा रहा है, जहां श्रद्धालु बैठ सकेंगे और आवागमन सुगम रहेगा.

864 करोड़ से किया जाएगा घाट का निर्माण

सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत उज्जैन में क्षिप्रा नदी के दोनों तटों पर लगभग 29 किलोमीटर लंबे आधुनिक घाट विकसित किए जा रहे हैं. करीब 864 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना में रिवर फ्रंट कॉरिडोर, 21 नए बैराज और कई स्थानों पर 15.5 मीटर चौड़े पक्के घाट बनाए जा रहे हैं. इन घाटों का उद्देश्य सिंहस्थ के दौरान आने वाले 30 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम स्नान सुविधा उपलब्ध कराना है.

बुनियादी सुविधा जुटा रहे-सिंहस्थ 2028 को देखते हुए उज्जैन में घाट, सड़क, पुल और अन्य बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को बेहतर व्यवस्था और सुगम दर्शन-स्नान की सुविधा मिल सके.

मुख्यमंत्री ने रामनवमी पर प्रदेशवासियों को दीं शुभकामनाएं

भोपाल. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राम नवमी के पावन पर्व पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भगवान श्रीराम का जीवन संयम, समर्पण, सहयोग और मूल्यों पर अडिग रहने के भाव से परिपूर्ण था. भगवान श्रीराम ने दृढ़ संकल्प के साथ अनाचार का विरोध करने और जीवन की कठिनाईयों का साहस से सामना करने की प्रेरणा दी. यह मध्यप्रदेशवासियों का सौभाग्य है कि अयोध्या की तरह चित्रकूट धाम और ओरछा तीर्थ यहां पर हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्म राम के जीवन और योगदान का स्मरण करवाते हैं.

कई शहरों में तापमान 38 डिग्री से अधिक

मौसम का गर्मी-बारिश का डबल अटैक

27 से 29 मार्च तक आंधी-बारिश का अलर्ट

भोपाल , 26 मार्च. मध्य प्रदेश में मौसम का मिजाज इन दिनों लगातार बदल रहा है. एक ओर जहां प्रदेश के कई शहरों में तापमान 38 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है, वहीं दूसरी ओर अब तीसरी बार बारिश और आंधी का दौर शुरू होने जा रहा है.

मौसम विभाग ने 27, 28 और 29 मार्च के लिए अलर्ट जारी किया है, जिससे साफ है कि गर्मी के बीच लोगों को एक बार फिर मौसम का बदला हुआ रूप देखने को मिलेगा.

गुरुवार तक प्रदेश में तेज गर्मी का असर बना रहने की संभावना है. खासतौर पर उज्जैन, भोपाल, सागर और नर्मदापुरम संभाग में तापमान अधिक रहने के आसार हैं. हाल ही में नर्मदापुरम प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 38.8 डिग्री दर्ज किया गया.

इसके अलावा रतलाम, खंडवा, खरगोन और रायसेन में भी तेज गर्मी का प्रभाव देखा गया. बड़े शहरों जैसे भोपाल, इंदौर, उज्जैन और जबलपुर में भी पारा 35 डिग्री से ऊपर बना हुआ है. हालांकि, 27 मार्च से पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के चलते मौसम अचानक करवट लेगा. इसके असर से प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है. इस सिस्टम का सबसे ज्यादा असर उज्जैन, ग्वालियर-चंबल और सागर संभाग में देखने को मिलेगा, जहां आंधी के साथ बारिश के आसार हैं. मार्च महीने में इससे पहले भी दो बार आंधी-बारिश का दौर आ चुका है.

खतरनाक उद्योगों में बाल श्रमिक मिले तो शून्य अंक मिलेंगे

- श्रम स्टार रेटिंग का किया गया है प्रावधान

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 मार्च. 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों का खतरनाक उद्योगों एवं प्रक्रियाओं में नियोजन पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया गया है. श्रम स्टार रेटिंग के तहत यदि किसी संस्थान में बाल श्रम अथवा बंधक श्रम पाया जाता है, तो जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उस संस्थान को शून्य अंक दिए जाएंगे.

इस संबंध में मप्र के सभी श्रम अधिकारियों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जिन संस्थानों में बाल या बंधुआ श्रमिक नियोजित नहीं हैं, उन्हें अन्य मापदंडों में कुछ कमी होने के बावजूद श्रम स्टार रेटिंग प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. बाल श्रम उन्मूलन के लिए श्रम विभाग द्वारा वेदा पहल के तहत लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसके तहत प्रत्येक शुक्रवार को नियमित समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है और अभियोजन मामलों की कड़ी निगरानी रखी जा रही है. सहायक श्रम आयुक्त, श्रमायुक्त राखी जोशी के अनुसार कानूनी प्रावधानों के तहत बाल श्रम अधिनियम, 1986 के तहत दोषी पाए जाने पर 20 हजार से 50 हजार रुपये तक जुर्माना और 6 माह से 2 वर्ष तक कारावास की सजा का प्रावधान है.

6.70 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का भंडारण

मार्कफेड की समीक्षा बैठक में दी गई जानकारी

प्रशासनिक संवाददाता

भोपाल, 26 मार्च. इस वर्ष 10.80 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों का भंडारण लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके विरुद्ध 23 मार्च तक 6.70 लाख मीट्रिक टन का भंडारण हो चुका है. किसानों को स्थानीय स्तर पर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित कराया जाएगा.

यह जानकारी गुरुवार को मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ यानी मार्कफेड कार्यालय में समीक्षा बैठक में संघ की गतिविधियों, उर्वरक वितरण व्यवस्था, वित्तीय प्रबंधन, परिसंपत्तियों के उपयोग एवं व्यवसाय विस्तार की समीक्षा बैठक के दौरान दी गई. इस दौरान सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग ने

कहा कि मार्कफेड को आत्मनिर्भर, आधुनिक एवं व्यावसायिक रूप से मजबूत संस्था बनाने के लिए सभी अधिकारी लक्ष्य आधारित कार्य करें. उन्होंने किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराने, बंद औद्योगिक इकाइयों को पुन: प्रारंभ करने, संपत्तियों की डिजिटल मैपिंग करने तथा गोदामों के पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. सारंग ने वित्तीय प्रबंधन की समीक्षा करते हुए बैंकों से प्राप्त ऋण एवं लंबित बकाया राशि की शीघ्र वसूली के निर्देश दिए, जिससे उर्वरक कंपनियों को भुगतान में कोई बाधा नहीं आए.

सीएम ने किया 506 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन

छिंदवाड़ा, 26 मार्च. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 506 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया साथ ही सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत प्रदेश के 7000 से अधिक श्रमिकों को 157 करोड़ और पेंशन योजना के हितग्राहियों को 463 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित.

इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना के तहत प्रदेश के 7000 से अधिक श्रमिकों को 157 करोड़ और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को 463 करोड़ से अधिक की राशि अंतरित की. इस दौरान छिंदवाड़ा जिले में विकास को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत कुल 105 विकास कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया. इन परियोजनाओं की कुल लागत 506.29 करोड़ रुपये है, जिसमें 153.93 करोड़ रुपये के 20 कार्यों का भूमिपूजन और 352.36 करोड़ रुपये के 85 कार्यों का लोकार्पण शामिल हैं. इनमें मुख्य कार्यों में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा तामिया - जुन्नारदेव मार्ग (राज्य मार्ग 41) पर 133 करोड़ रुपए की लागत के 28.31 किमी का पुनर्निर्माण एवं उन्नयन कार्य और जिले के सबसे लंबे आर.ओ. बी के निर्माण कार्य, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत 42.12 करोड़ रुपए की लागत के 90 ग्रामों में नल जल योजना कार्य, मध्य प्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम भोपाल द्वारा 37.72 करोड़ रुपए की लागत के 24 एन.जी.ओ एवं 144 आरक्षक (बहु मंजिला) आवासगृह पुलिस लाइन छिंदवाड़ा के निर्माण कार्य और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकासखंडों के अंतर्गत 56.23 करोड़ रुपए की लागत के 7 शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 5 छात्रावासों के निर्माण कार्य का लोकार्पण शामिल है. मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आज जिले को 506 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों की सौगात दी गई है. विकास के मामले में छिंदवाड़ा अब लगातार आगे बढ़ता जाएगा. विकास के लिए हमारा और आपका संकल्प लगातार चलता रहेगा. सरकार के पास पैसों की कोई कमी नहीं है.

सिंगल क्लिक से मुख्यमंत्री संबल योजना के तहत 7000 से अधिक श्रमिकों को 157 करोड़ और पेंशन योजना के हितग्राहियों को 463 करोड़ की राशि अंतरित

इन कार्यों के निर्माण का हुआ भूमिपूजन

मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत 153.94 करोड़ रुपए की लागत के कुल 20 कार्यों का भूमिपूजन किया गया. इनमें लोक निर्माण विभाग के 12 कार्यों पर सर्वाधिक 95.85 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके अतिरिक्त राजस्व विभाग के 3 कार्य लागत 27.34 करोड़ जिनमें संयुक्त तहसील कार्यालय भवन जुन्नारदेव, अमरवाड़ा व परासिया, विद्युत वितरण कंपनी के 2 कार्य लागत 2.68 करोड़ जिनमें नवीन 33/11 के.व्ही. उपकेंद्र परासिया व छिंदवाड़ा, उच्च शिक्षा विभाग का 1 कार्य (2.01 करोड़) और ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं के अंतर्गत 19.50 करोड़ लगात के 80 सामुदायिक भवन व 6.56 करोड़ लागत के 91 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी लैब का निर्माण शामिल है.

झाबुआ में जिला पंचायत अधिकारी रिश्वत लेते गिरफ्तार

इंदौर. भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए इंदौर लोकायुक्त इकाई ने झाबुआ जिला पंचायत के अधिकारी को ट्रेप कर पकड़ लिया. उप पुलिस अधीक्षक आनंद चौहान ने बताया कि आवेदक मांजुसिंह परमार, जो झाबुआ जिले के ग्राम रुपाखेडा के निवासी और जिला पंचायत में डाटा एंट्री ऑपरेटर थे, की शिकायत पर कार्रवाई की गई. बताया कि दस मार्च को उनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी. जब आवेदक पुनः ज्वाइनिंग के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधक (आरजीएसए) यश पंवार से मिले, तो आरोपी ने उन्हें पद पर बहाली के एवज में 15,000 की रिश्वत की मांग की. शिकायत का सत्यापन करने पर तथ्य सही पाए गए और आरोपी यश पंवार के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया.

प्रवेश नवीनीकरण के लिए खुला पोर्टल

28 मार्च तक विद्यार्थी ले सकेंगे लाभ

भोपाल, 26 मार्च. उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के विद्यार्थियों के व्यापक शैक्षणिक हितों एवं भविष्य की सुरक्षा को सर्वोपरि रखते हुए, स्नातक (द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष) तथा स्नातकोत्तर (तृतीय सेमेस्टर) के परीक्षार्थियों के लिए प्रवेश नवीनीकरण के लिए विशेष अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया है.

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी उच्च शिक्षा डॉ दिवा मिश्रा ने बताया कि यह विशेष सुविधा उन विद्यार्थियों के लिए प्रदान की गई है, जो प्रवेश नवीनीकरण के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत पूरक परीक्षा परिणामों की घोषणा के कारण नियत समय-सीमा में अपनी प्रवेश औपचारिकताएं पूर्ण करने से वंचित रह गए थे. प्रवेश पोर्टल को 28 मार्च 2026 तक सक्रिय किया जा रहा है. संबंधित विद्यार्थी, इस विस्तारित अवधि का लाभ उठाकर अपने प्रवेश नवीनीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूर्ण करें.

प्राचार्यों को भी जारी हुए निर्देश

समस्त शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों के शेष पात्र विद्यार्थियों का त्वरित चिन्हांकन कर, उनका प्रवेश नवीनीकरण एवं शुल्क समय सीमा में जमा करवाना सुनिश्चित करें। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सुविधा सीमित अवधि के लिए ही उपलब्ध होगी, इसलिए सभी संबंधित विद्यार्थी एवं संस्थान निर्धारित समय-सीमा का कड़ाई से पालन करें, जिससे किसी भी विद्यार्थी की शैक्षणिक निरंतरता बाधित न हो।

समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी

विशेष संवाददाता

भोपाल, 26 मार्च. मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने संविदा कर्मचारियों की स्थिति और युवाओं से जुड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रबंधन को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है.

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक असंवेदनशीलता के कारण लाखों कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि युवाओं का भविष्य भी अनिश्चितता में है. पटवारी ने कहा कि संविदा नीति 2023 के पालन को लेकर विभागों, निगमों और मंडलों से रिपोर्ट तलब करना इस बात का संकेत है कि अब तक कर्मचारियों को उनके अधिकार नहीं मिल पाए हैं. उन्होंने इसे प्रशासनिक विफलता करार दिया. उन्होंने बताया कि प्रदेश में करीब 1.5 से 2 लाख संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं, लेकिन उनके भविष्य को लेकर सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है. नीति लागू होने के बावजूद ग्रेच्युटी, अनुकंपा नियुक्ति और सामाजिक सुरक्षा जैसे लाभ पूरी तरह नहीं दिए गए हैं. उन्होंने कहा कि केवल बार-बार रिपोर्ट मंगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, इसके लिए ठोस निर्णय जरूरी हैं. एक अन्य मुद्दे पर पटवारी ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और पुलिस विभाग की उप निरीक्षक भर्ती की मुख्य परीक्षा को 26 अप्रैल को एक ही दिन आयोजित करने के फैसले की आलोचना की. उन्होंने कहा कि हजारों अभ्यर्थी, जिन्होंने दोनों परीक्षाओं के लिए आवेदन किया है, अब दुविधा में हैं. उन्होंने मांग की कि कर्मचारियों को तुरंत लाभ दिए जाएं, स्पष्ट नीति बनाई जाए और परीक्षाओं में से किसी एक की तिथि बदली जाए. साथ ही चेतावनी दी कि जल्द निर्णय नहीं होने पर प्रदेशभर में आंदोलन किया जाएगा.

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्रा. लि. हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशुतोष उपाध्याय द्वारा 6/54, फिरोज गांधी प्रेस काम्प्लेक्स, इंदौर से प्रकाशित एवं नवभारत प्रेस भोपाल प्रा.लि. , फिरोज गांधी प्रेस कॉम्प्लेक्स इंदौर से मुद्रित. समूह संपादक क्रांति चतुर्वेदी*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन/फैक्स- 4096718 RNI Reg. No.7590/60